भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3693

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन नीति

3693. श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के बीच समझौता ज्ञापन के परिणामों को विभिन्न प्रकार की नीतियों के परिणामों को राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन नीतियों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में कार्बन बाजार की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(ग) क्या इस सहयोग के माध्यम से कार्बन ऑफसेट तंत्र को अपनाने वाले उद्योगों के लिए कोई प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की गई हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): जी, नहीं, इस समझौता ज्ञापन के तहत इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) की भूमिका केवल क्षमता निर्माण और ज्ञान सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अनुसार, भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को जून, 2023 में और संशोधन को दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया। इस योजना में दो तंत्र अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र परिभाषित किए गए हैं। अनुपालन तंत्र में, बाध्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के प्रत्येक अनुपालन साइकल में निर्धारित ग्रीन हाउस गैस

उत्सर्जन में कमी के मानदंडों का अनुपालन करेंगी। ऑफसेट तंत्र में, गैर-बाध्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी या उसे हटाने या उसका परिहार के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की ट्रेडिंग के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या उसका परिहार करना है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की परिकल्पना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को उत्सर्जन को कम करने की आर्थिक लागत को कम करने की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।

(ग) एवं (घ): इस सहयोग के माध्यम से कोई प्रोत्साहन योजना तैयार नहीं की गई है।

*****